वृक्षों से 'बेवफाइ' विनाशकारी

महेश तिवारी

पृथ्वी द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों में हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, ईंधन, पौधे और पशु-पक्षी शामिल हैं। इन संसाधनों की देखभाल करना और इनका सीमित उपयोग करके ही प्रकृति का संरक्षण किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को सुंदर प्राकृतिक परिवेश उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन वर्तमान दौर में विकास की अंधी दौड़ में इनके संरक्षण के प्रति लोग वफादार नहीं, जिस कारण कहीं तापमान में तीव्र वृद्धि, कहीं मूसलाधार बारिश और कहीं जलजला आ रहा है। इस चराचर जगत में हर वस्तु की अहमियत है, इसलिए इस धरा पर हर उस वस्तु के प्रति सामंजस्य बनाकर चलना होगा। जो जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण हमारे जीवन और अस्तित्व का आधार हैं। लेकिन आधुनिक सभ्यता की उन्नति ने हमारे ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत बुरा असर डाला है। इसलिए आज प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नितांत आवश्यक बनता जा रहा है। आधुनिक समय में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप जंगलों का विनाश बढता जा रहा है। जो आने वाले वक्त में मुसीबतों को न्यौता देने वाला है। लोग विकास की चाहत में शायद यह भूल गए हैं, कि पेड़ हमारी जिंदगी का आधार हैं। पेड़ों से हमें जीवनदायिनी वायु ही नहीं मिलती बल्कि इस धरा पर जो संतुलन बनता है। उसका वाहक वृक्ष ही बनते हैं। साथ में पेड़ों और जंगलों से हम अपनी काफी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं।

पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2017 में एक फ़ीसद वन क्षेत्र बढ़ा है। लेकिन अगर राज्यों में वन घट रहे हैं तो यह शुभ संकेत नहीं। फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भले ही 2015 से 2017 के दौरान देश में 6778 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया हो, लेकिन मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र में कमी आना चिंता का विषय है। वह भी यह उस दरमियान में हो रहा है, जब मध्यप्रदेश की रहनुमाई व्यवस्था वृक्ष को लगाने और बचाने के लिए तत्परता से आगे आ रही है। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपदा, जंगल और ज़मीन ही होती है - लेकिन अगर सूबे में पिछले दो वर्षों में 12 वर्ग किलोमीटर जंगल घट गए। तो यह आने वाले वक्त के लिए ख़तरे की घन्टी है। सूबे में जंगल की कटाई का मुख्य कारण खेती के लिए वन की कटाई, डूब क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए, जंगलों के पास के शहरों के विस्तार के लिए, हाईवे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना औऱ वैध-अवैध माइनिंग है।

संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट कहती है, कि हमारे देश में रोपे जाने वाले पौधों में से 35 फ़ीसद बढ़ नहीं पाते। यह चिंता की बात है। साथ में जो घनघोर वन क्षेत्र वन्यजीवों की शरणस्थली होते हैं कम होना भी ठीक नहीं। ये हालात प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ अगर पूर्वोत्तर के छह राज्यों में वन क्षेत्र घटा है, तो चेत जाना चाहिए। एक फ़ीसद वन बढ़ोतरी पर इतराया नहीं जा सकता, क्योंकि इसबार 589 से बढ़ाकर जिलों की संख्या 633 हो गई थी, तो अगर मानव समाज को अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छा समाज देना है, तो देश और प्रदेश हर जगह वन क्षेत्र को बढ़ाने पर बल देना होगा। शहरीकरण और विकास के नाम पर वनों और वृक्षों की बलि रोकना होगी। हर कार्य रहनुमाई व्यवस्था का नहीं होता- समाज को भी कुछ जिम्मेदारी उठानी होगी। फ़िर से 'चिपको आंदोलन' की तरफ़ देश और समाज को बढ़ना होगा।

जंगलों के ही कारण बारिश होती है, लेकिन तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव अपनी जरूरतों के लिए अंधाधुंध जंगलों का विनाश कर रहा है। इसी कारण से आज जंगलों का अस्तित्व खतरे में है। नतीजतन मानव जीवन खतरे में पड़ता दिख रहा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर वर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र काटे जाते हैं। और भारत में भी वनों की कटाई तेजी से बढ़ रही है। शहरीकरण का दबाव, बढ़ती आबादी और तेजी से विकसित होने की चाहत, औऱ जीवन में हर सुख- सुविधा की चाहत ने हमें हरी-भरी जिंदगी से वंचित करना शुरु कर दिया है। वनों की कटाई से मिट्टी, पानी और वायु क्षरण होता है। जो धरा के संतुलन को बिगाड़ने का कार्य

करती है। शायद यह आज का मानव भूल गया है। घटते जंगल और पेड़-पौधे ही बाढ़-सूखा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग के साथ पशु-पक्षियों की प्रजातियों की विलुप्तिकरण का कारण हैं।

जल स्तर में कमी के साथ आदिवासियों के जीवन चक्र को रोकने का कार्य वनों की बढ़ती विनाशलीला ने किया है। आज के दौर में भले ही आधुनिक समाज की सोच ने जंगल के विनाश को जीवन के लाभ का उद्देश्य बना लिया है, लेकिन उन आदिवासियों का क्या जिनके लिए जंगल ही जीवन शैली है। साथ-साथ आजीविका का साधन भी। ऐसा माना जाता है आदिवासी, प्रसव के दौरान पेड़ों की छाल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा छाल हटाने से पहले वे वृक्षों को चावल, दाल की भेंट देते हैं, और फिर वे वृक्ष भगवान की प्रशंसा में धूप और मंत्रों के साथ पेड़ की पूजा करते हैं। तो अगर ऐसे जंगल नष्ट होते रहे तो ऐसी जनजातियों औऱ उनकी प्रथाओं का क्या होगा। तो अगर वृक्ष और जंगल ही जीवन का आधार है, तो उसे अपने शरीर से बढ़कर महत्वा देनी होगी।

भारत अगर विश्व में जैव विविधता में 17 वें स्थान पर आता है, तो वह आज के वक्त में जनजागरण से ही बचा रह सकता है। आज वनों के विस्तार के लिए सम्यक नीति और नियत की ज़रूरत है, तो क्यों न जंगल और वृक्षों की रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य हो, बल्कि उसे आज का समाज अपना धर्म बनाएं। और अगर सिक्किम देश के सबसे स्वच्छ और हरित प्रदेशों में शुमार है, तो हम भी कर सकते हैं। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य का लगभग 47 फ़ीसद हिस्सा वनाच्छादित है। यहां वनों से रिश्ता रखने की पुरानी परम्परा भी रही है। सिक्किम सरकार ने तो वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ते की सरकारी मान्यता दे दी है। यह उस प्रदेश में हो रहा है, जो देश का सबसे वनाच्छादित राज्य है, तो क्या अन्य राज्यों और देश को इससे कुछ सीख लेने की ज़रूरत नहीं? इसके अलावा अब तो फिलीपींस, जहां की सरकार ने पर्यावरण बचाने के लिये एक अनोखा कानून लागू किया है। फिलीपींस सरकार का यह अनोखा नियम लागू करने का तर्क यह है, कि देश में भारी मात्रा में वनों की कटाई से देश का कुल वन आवरण 70 फीसदी से घटकर 20 फीसदी पर आ गया है।

इस कानून के तहत सरकार ने देश में एक साल में 175 मिलियन से अधिक पेड़ लगाने, उनका पोषण करने और उन्हें विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अनोखा नियम फिलीपींस सरकार का यह है कि हर छात्र को अपने स्नातक की डिग्री पाने के लिए कम से कम 10 पेड़ लगाना अनिवार्य है। जिस नियम को 'ग्रेजुएशन लीगेसी फॉर द इन्वायरन्मेंट एक्ट' नाम दिया है। जिसे फिलीपींस की संसद में सर्वसम्मति से पास किया जा चुका है। यह कानून कॉलेजों, प्राथमिक स्तर के स्कूलों और हाई स्कूल के छात्रों के लिए भी लागू होगा। फिलीपींस सरकार की मानें तो वहां की सरकार ने इसके लिए वो इलाके भी चुन लिये हैं, जहां पेड़ लगाए जाएंगे। चयनित क्षेत्रों में मैनग्रोव वनक्षेत्र, सैन्य अड्डे और शहरी क्षेत्र के इलाके शामिल हैं। स्थानीय सरकारी एजेंसियों को इन पेड़ों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में दिन-प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ते पर्यावरण की रक्षा वृक्ष ही करते हैं। यह विश्व पटल के देश भी मानते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर साथ ही साथ पेड़ संस्कृति और धर्म को भी ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ों को सहेजना तो हमें और हमारे देश के रहवासियों को भी पड़ेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक भारतीय के हिस्से में सिर्फ़ 24 पेड़ बचें हैं। जो कहीं न कहीं भविष्य की भयावह स्थिति का संकेत अभी से दे रहें। ऐसे में हमें समय रहते इसके प्रति सचेत होना पड़ेगा। (प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।